



न्यायिक नरिणयों का आर्थिक प्रभाव

चर्चा में क्यों

हाल ही में [नीतिआयोग](#) ने अनुसंधान संगठन 'उपभोक्ता एकता और ट्रस्ट सोसायटी (Consumer Unity and Trust Society- CUTS) अंतर्राष्ट्रीय' को न्यायालयों एवं न्यायाधिकरणों द्वारा दिये गए विभिन्न नरिणयों के 'आर्थिक प्रभाव' तथा 'न्यायालयों व न्यायाधिकरणों की ['न्यायिक सक्रियता'](#) पर एक अध्ययन करने के लिये कहा है।

- **न्यायिक सक्रियता:** इसका तात्पर्य न्यायपालिका द्वारा सरकार के अन्य दो अंगों (वधायिका और कार्यपालिका) को उनके संवैधानिक कर्तव्यों के निर्वहन के लिये बाध्य करने हेतु नभार्ई गई मुखर भूमिका से है। इसे "न्यायिक गतिशीलता" के रूप में भी जाना जाता है। यह "न्यायिक संयम" के बलिकूल विपरीत है, जिसका अर्थ है न्यायपालिका द्वारा आत्म-नियंत्रण बनाए रखना।

प्रमुख बडि

संगठन का संचालन:

- यह अध्ययन जयपुर-मुख्यालय **CUTS** (उपभोक्ता एकता और ट्रस्ट सोसायटी) सेंटर फॉर कॉम्पटिशन, इन्वेस्टमेंट एंड इकोनॉमिक रेगुलेशन द्वारा किया जाना है, जिसकी उपस्थिति अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर है।
- यह एक पंजीकृत, मान्यता प्राप्त, गैर-लाभकारी, गैर-पक्षपातपूर्ण, गैर-सरकारी संगठन (**NGO**) है जो सामाजिक न्याय तथा आर्थिक इक्वटी की सीमा के भीतर और इसके अलावा भी उसका अनुसरण करता है।

उद्देश्य:

- अध्ययन का उद्देश्य "न्यायपालिका को उसके द्वारा दिये गए नरिणयों के आर्थिक प्रभाव के बारे में संवेदनशील बनाने हेतु विवरण प्रदान करना है।"
- इसका एक उद्देश्य नरिणयों के आर्थिक प्रभाव का लागत-लाभ विश्लेषण करना भी है।

परियोजनाओं का अध्ययन:

- इसका प्रयोजन [सर्वोच्च न्यायालय](#) (Supreme Court- SC) या [राष्ट्रीय हरति अधिकरण](#) (National Green Tribunal- NGT) के न्यायिक नरिणयों द्वारा "प्रभावति" पाँच प्रमुख परियोजनाओं का अध्ययन करना है।
 - विश्लेषण की जाने वाली परियोजनाओं में गोवा के मोपा में एक हवाई अड्डे का निर्माण, गोवा में लौह अयस्क खनन पर रोक और तमलिनाडु के थूथुकुडी में स्टारलाइट कॉपर प्लांट को बंद करना शामिल है।
 - राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में [रेत खनन](#) और निर्माण गतिविधियों से संबंधित NGT के अन्य फैसले हैं।

प्रक्रिया:

- यह परियोजना के बंद होने के कारण प्रभावति लोगों, पर्यावरणविद, विशेषज्ञों के साक्षात्कार साथ-साथ बंदी के व्यावसायिक आकलन की योजना बना रहा है।

महत्त्व:

- नरिणयों का उपयोग वाणिज्यिक न्यायालयों, NGT, उच्च न्यायालयों और सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के लिये एक प्रशिक्षण इनपुट के रूप में किया जाएगा।
- यह अपने नरिणयों में "न्यायपालिका द्वारा आर्थिक रूप से ज़मिमेदार दृष्टिकोण" को बढ़ावा देने के लिये नीतिनिर्माताओं के बीच सार्वजनिक संवाद में योगदान देगा।
- यह अध्ययन नीतिआयोग द्वारा शुरू की गई व्यापक योजना का भी एक हिस्सा है जिसके तहत वह एक न्यायिक प्रदर्शन सूचकांक स्थापित करना चाहता है, जो ज़िला न्यायालयों और अधीनस्थ स्तरों पर न्यायाधीशों के प्रदर्शन को मापेगा।

पूरव अधययन:

- वर्ष 2017 में CUTS अंतरराष्ट्रीय ने कसी भी राजमार्ग के 500 मीटर के भीतर शराब की दुकानों पर प्रतिबंध लगाने के सर्वोच्च न्यायालय के नरिणय के आर्थिक प्रभाव पर एक मूल्यांकन अधययन भी कयिा था ।
- अधययन से पता चलता है कि जिनि मामलों में पर्याप्त सामाजिक और आर्थिक आयाम शामिल हैं, उनका आकलन करने के लयि वसितार से यह अधययन करने की आवश्यकता है कि कयिा वे पूरव की तरह लागू करने के योग्य हैं और कयिा अर्थव्यवस्था को हुए नुकसान की परकिल्पना की गई है ।
- ऐसा तब कयिा जा सकता है जब न्यायालयों ने इन पहलुओं का अधययन करने के लयि वशिषज्ज समतियिों का गठन कयिा हो और जो नरिणय सुनाए जाने से पहले लागत/लाभों का वशिषण करने के लयि अर्थशास्त्रियिों को संलग्न कर सकते हैं ।
- सर्वोच्च न्यायालय ने पूरव मामलों के लयि ऐसे वशिषज्ज समूह समतियिों की स्थापना की थी जैसे- वर्ष 2014 में न्यायमूरत के.एस. राधाकृष्णन की अधयकषता में गठति सड़क सुरकषा पर सर्वोच्च न्यायालय की समति और वर्ष 2015 में भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (Board of Control for Cricket in India- BCCI) के भीतर सुधारों हेतु जस्टिस [लोद्दा समति](#) का गठन ।

Obstacle course

Some projects/companies which have hit the hurdle grounds

MOPA AIRPORT, GOA

The SC in 2019 suspended environmental clearance but lifted it in Jan. 2020 after imposing several conditions



STERLITE COPPER, THOOTHUKUDI, T.N.

The SC in Dec. rejected a proposal made by Vedanta to operate its closed copper plant. The Madras HC and the T.N. govt. had ordered the closure of the plant



IRON ORE MINING, GOA

In 2018, the SC quashed 88 mining leases for violation of mining procedures and asked the State govt. to issue fresh leases



SAND MINING, UTTAR PRADESH

The National Green Tribunal in 2013 suspended sand mining operations and directed that environmental clearances be obtained from authorities



CONSTRUCTION ACTIVITIES AROUND DELHI

The NGT imposed a ban on construction activities but specific instances are not known



//

स्रोत: इंडियन एक्सप्रेस